उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 6 | अंक 22 | 16-30 नवंबर 2023 | ₹ 20/-

उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध का जबर्दस्त विरोध

- गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ कार्रवाई पर गतिरोध
- बांग्लादेश में विपक्ष के 139 प्रमुख नेताओं को सजा
- सऊदी अरब द्वारा गाजा में पूर्ण युद्धविराम की मांग
- नीदरलैंड के चुनाव में इस्लाम विरोधी नेता को भारी सफलता

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष: 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशक: मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध का जबर्दस्त विरोध 04
लोकसभा के चुनाव में भाजपा को सशर्त समर्थन देने की घोषणा 08
उर्दू मीडिया द्वारा संघ प्रमुख की आलोचना 10
गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ कार्रवाई पर गतिरोध 14
एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में रामायण-महाभारत को शामिल करने की सिफारिश 16

विश्व

बांग्लादेश में विपक्ष के 139 प्रमुख नेताओं को सजा 18
नीदरलैंड के चुनाव में इस्लाम विरोधी नेता को भारी सफलता 20
भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकालने की मांग 21
अमेरिका द्वारा आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों पर प्रतिबंध 24
पाकिस्तान ने अफगान माल को भेजने पर लगाई रोक 25

पश्चिम एशिया

सऊदी अरब द्वारा गाजा में पूर्ण युद्धविराम की मांग 27
क्या गाजा में युद्धविराम के पीछे चीन का हाथ है? 29
ईरान से अफगान नागरिकों के निष्कासन का अभियान 31
कतर में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों की फांसी के खिलाफ अपील 32
यमन में भारतीय नर्स की मौत की सजा के खिलाफ अपील खारिज 33

सारांश

उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाणपत्र जारी करने वाले चार मुस्लिम संगठनों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त हलाल प्रमाणित उत्पादों के खिलाफ भी राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया है। इस संबंध में दर्जनों स्थानों पर छापे मारे गए हैं और आरोपियों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। लखनऊ के एक कार्यकर्ता ने पुलिस में यह शिकायत दर्ज कराई है कि हलाल प्रमाणपत्र देने वाले संस्थाओं द्वारा संबंधित व्यापारियों और उनकी फर्मों से मोटी रकम वसूली जाती है और उस राशि का इस्तेमाल भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने इस केस की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से मुस्लिम संगठनों और उसके नेताओं में भारी नाराजगी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठनों ने सरकार के इस फैसले को इस्लाम और शरिया के विरुद्ध बताया है और सरकार पर आरोप लगाया है कि मुस्लिम दुश्मनी की भावना के तहत इस प्रतिबंध को लगाया गया है।

बरेलवी संप्रदाय के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने आगामी लोकसभा के चुनावों में मोदी सरकार और भाजपा का समर्थन करने का संकेत दिया है, मगर इसके बदले में उन्होंने एक कड़ी शर्त भी रख दी है। उनका कहना है कि अगर मोदी सरकार इजरायल से अपने संबंधों को तोड़कर फिलिस्तीन के साथ संबंध स्थापित करती है तो बरेलवी संप्रदाय आने वाले चुनाव में उसका समर्थन करेगा। इसमें संदेह नहीं है कि बरेलवी संप्रदाय को मुसलमानों के एक बड़े वर्ग का समर्थन प्राप्त है। यह संप्रदाय सूफियों को मानता है और उनके दरगाहों पर हाजिरी देकर चादरें भी चढ़ाता है। बरेलवी और देवबंदी संप्रदाय के बीच के मतभेद कम-से-कम 200 साल पुराने हैं। देवबंदी संप्रदाय इस्लाम की वहाबी विचारधारा में आस्था रखता है और वह दरगाहों पर हाजिरी देने और उन पर चादर आदि चढ़ाने को इस्लाम के विरुद्ध मानता है। इसके साथ ही दोनों संप्रदाय एक दूसरे के खिलाफ फतवे जारी करते रहे हैं। गौरतलब है कि साल 1992 में जब अयोध्या के विवादित ढांचे को ध्वस्त किया गया था तो सरकार के खिलाफ मुसलमानों में भारी आक्रोश था। इसे देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने बरेलवी संप्रदाय का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया था और वे इस संबंध में आला हजरत की दरगाह पर हाजिरी देने के लिए बरेली भी गए थे, मगर बाद में नरसिम्हा राव के सत्ता से बेदखल होने के कारण यह मामला खटाई में पड़ गया था।

इजरायल और हमास के बीच अस्थाई युद्धविराम हो गया है। सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम देश अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अमेरिका इजरायल पर दबाव डालकर उसे गाजा में स्थाई युद्धविराम लागू करने के लिए तैयार करे, मगर अभी तक उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली है। कुछ मुस्लिम देशों ने यह भी दावा किया है कि चीन के राष्ट्रपति के प्रयासों के कारण अमेरिका को इजरायल पर युद्धविराम के लिए दबाव डालना पड़ा था। गौरतलब है कि इससे पहले चीन के राष्ट्रपति ने इस युद्धविराम के लिए माहौल बनाने हेतु अरब और मुस्लिम देशों के कई विदेश मंत्रियों को वार्ता के लिए चीन की राजधानी बीजिंग में बुलाया था। इसके बाद चीनी राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ वार्ता करने के लिए अमेरिका भी गए थे। हालांकि, अमेरिका ने युद्धविराम में चीन की भूमिका का कोई संकेत नहीं दिया है, इसलिए यह कहना कठिन है कि इस युद्धविराम के पीछे विश्व की किन शक्तियों का हाथ है।

पाकिस्तान के बाद अब ईरान ने भी देश में अवैध रूप से रहने वाले अफगान नागरिकों के निष्कासन का अभियान तेज कर दिया है। अफगानिस्तान के सूत्रों के अनुसार अब तक चार लाख से अधिक अफगान नागरिकों को ईरान से निष्कासित किया जा चुका है। ईरान का यह दावा है कि ये अफगान नागरिक देश में आतंकवाद की ज्वाला को भड़काने में अपनी भूमिका निभाते हैं। अफगानिस्तान सरकार और संयुक्त राष्ट्र ने यह आरोप लगाया है कि विदेशों से अफगान नागरिकों को जबरन निष्कासित करने का अभियान चलाया जा रहा है, मगर ईरान और अफगानिस्तान दोनों ने उनके इन आरोपों का खंडन किया है। उनका दावा है कि वे उनके देशों में अवैध रूप से रहने वाले अफगान नागरिकों को निष्कासित करने के लिए यह अभियान चला रहे हैं।

हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध का जबर्दस्त विरोध

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हलाल प्रमाणित उत्पादों पर जो पाबंदी लगाई है उसका मुसलमानों द्वारा जबर्दस्त विरोध किया जा रहा है।

इंकलाब (20 नवंबर) के अनुसार पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल प्रमाणित उत्पादों पर जो प्रतिबंध लगाया है उसके तहत उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पर हलाल प्रमाणित दवाईयों, चिकित्सा उपकरणों, खाद्य सामग्रियों, सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पाद, भंडारण, वितरण, खरीद और बिक्री करने पर संबंधित व्यक्ति या फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि विदेशों में निर्यात होने वाले उत्पादों को इस पाबंदी से मुक्त रखा गया है। बताया जाता है कि उत्पादों के हलाल प्रमाणीकरण पर प्रतिबंध से संबंधित कानून की कुछ धाराओं के तहत छह साल से लेकर उम्रकैद और जुर्माने की सजा भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त हलाल प्रमाणित उत्पादों की जांच के लिए जांच समितियां गठित करने का भी निर्देश दिया गया है। ये समितियां दुकानों और शॉपिंग मॉल में छापा मारकर हलाल प्रमाणित उत्पादों को बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। पिछले दिनों डेयरी उत्पाद, शक्कर, बेकरी उत्पाद, पेपरमिंट ऑयल, नमकीन और खाद्य पदार्थों आदि को हलाल प्रमाणपत्र देने वाले संगठनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है।

इस संबंध में उत्तर प्रदेश की खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभाग की मुख्य सचिव अनीता सिंह की ओर से अधिसूचना भी जारी की गई है। इस अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में हलाल प्रमाणीकरण का लेबल लगे उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त दवाईयां, चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन भी शामिल हैं। अभी तक इन उत्पादों को पैकिंग करके उस पर हलाल प्रमाणित लेबल लगाकर उन्हें बाजारों में

बेचा जा रहा था। सरकार का कहना है कि इन उत्पादों में हलाल प्रमाणीकरण की कोई जरूरत नहीं है और यह भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल है। जबकि हलाल प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सरकार की ओर से कोई विधिवत कानून या नियम नहीं है और न ही औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत ही हलाल प्रमाणीकरण की कोई जरूरत है। ऐसी स्थिति में यदि किसी दवाई, चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधनों की पैकिंग पर हलाल प्रमाणित लेबल लगाया जाता है तो यह इस कानून का उल्लंघन है और इस कानून में सजा का भी प्रावधान है। सरकार का मानना है कि हलाल प्रमाणीकरण एक समानांतर व्यवस्था है, जोकि उत्पादों के स्तर के बारे में संदेह पैदा करता है और यह खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन करता है।

गौरतलब है कि हलाल प्रमाणपत्र जारी करने वाले मुस्लिम संस्थाओं जैसे चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की जमीयत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट, मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया और जमीयत उलेमा, महाराष्ट्र के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इसमें शिकायतकर्ता ने धर्म के नाम पर एक विशेष धर्म से संबंधित उपभोक्ताओं को हलाल प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने और आर्थिक लाभ पहुंचाने की शिकायत की थी।

इंकलाब (21 नवंबर) के अनुसार लखनऊ के हजरतगंज थाने में हलाल प्रमाणपत्र जारी करने वाले कुछ संगठनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। पुलिस की साइबर सेल और गुप्तचर विभाग ने इन संगठनों के कार्य और फंडिंग की जांच तेज कर दी है। बताया जाता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सिमी से इन संस्थाओं के संपर्क और इनके आय के स्रोत के बारे में जांच की जा रही है। इसके साथ ही विदेशों से आने वाली धनराशि का राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने के बारे में मिली शिकायतों की भी जांच की जा रही है। लखनऊ के ऐशबाग इलाके के निवासी शैलेंद्र कुमार शर्मा की ओर से लखनऊ के हजरतगंज थाने में हलाल प्रमाणपत्र जारी करने वाले संगठनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद राज्य की गुप्तचर एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। शिकायतकर्ता का यह आरोप है कि ये संगठन जनता के ईमान से खेल रहे हैं और बिना किसी कानूनी अधिकार के हलाल प्रमाणपत्र जारी करके मोटी आमदनी कर रहे हैं और यह धनराशि देशद्रोही तत्वों व आतंकी संगठनों को उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस शिकायत के मिलने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इन संगठनों द्वारा हलाल प्रमाणपत्र जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिसूचना जारी करने वाले विभाग की मुख्य सचिव अनीता सिंह ने इंकलाब को बताया कि पहले हलाल प्रमाणीकरण सिर्फ मांस के लिए इस्तेमाल होता था, मगर हाल के कुछ वर्षों में इसका इस्तेमाल सौंदर्य सामग्री, चीनी, तेल और खाद्य पदार्थों में भी शुरू हो गया है।

इंकलाब के इसी अंक में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एफएसडीए की टीमों ने राज्य भर में जांच का कार्य शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि इन विभागों ने लाखों रुपये का सामान जब्त किया है और इस संबंध में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं।

इंकलाब (23 नवंबर) के अनुसार हलाल प्रमाणित उत्पादों की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट, दिल्ली के अधिकारी नियाज अहमद फारुकी ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश से जो गैर-मांस उत्पाद निर्यात किए जाते हैं, ट्रस्ट सिर्फ उन्ही उत्पादों को हलाल होने का प्रमाणपत्र जारी करता है। उन्होंने बताया कि

स्थानीय स्तर पर बेचे जाने वाले उत्पादों के लिए ट्रस्ट की ओर से हलाल प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता। समाचारपत्र ने यह भी दावा किया है कि शैलेंद्र कुमार शर्मा नामक जिस व्यक्ति ने यह शिकायत दर्ज करवाई है, वह भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूर्व पदाधिकारी है। इस शिकायत के मिलने के बाद विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने इस केस की जांच के लिए एसटीएफ का गठन किया है, जिसके प्रमुख अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विशाल विक्रम सिंह हैं और उनकी टीम में पांच अन्य अधिकारी भी शामिल हैं।

इंकलाब (27 नवंबर) के अनुसार इस मामले का स्पष्टीकरण देते हुए एफएसडीए की अतिरिक्त मुख्य सचिव अनीता सिंह ने कहा है कि हलाल प्रमाणित उत्पादों को गलत पैकिंग और लेबलिंग की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए सरकार द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, शिकायत मिलने पर मामले को एडीएम की अदालत में भेजकर संबंधित व्यापारियों पर आर्थिक दंड लगाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो छापे मारे गए हैं या मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसमें अभी तक किसी को जेल नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा कि परचून व्यापारी एसोसिएशन ने हलाल प्रमाणित उत्पादों को दुकानों और शॉपिंग सेंटरों से हटाने के लिए 15 दिन का समय मांगा था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

रोजनामा सहारा (22 नवंबर) के अनुसार पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने राज्य में एफएसडीए की टीमों द्वारा छापे मारे जाने की शिकायत अल्पसंख्यक आयोग से की है।

इंकलाब (24 नवंबर) के अनुसार हलाल प्रमाणित उत्पादों के खिलाफ राजनीतिक अभियान में तेजी आ रही है। उत्तर प्रदेश के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी हिंदू सेना नामक संगठन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराके उन संगठनों के

खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है, जो हलाल प्रमाणपत्र देकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं।

उर्दू टाइम्स (19 नवंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाणीकरण को लेकर उत्पन्न विवाद पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सख्त रोष प्रकट किया है और यह दावा किया है कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट द्वारा जो प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं उनका संबंध देश और विदेश में हलाल प्रमाणित वस्तुओं के आयात और निर्यात की आवश्यकताओं से है। इसे किसी भी तरह का राजनीतिक रंग देना शरारतपूर्ण कदम है। वर्तमान समय में विश्व स्तर पर हलाल प्रमाणित उत्पादों की बहुत मांग है और विश्व बाजार में अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए भारतीय कंपनियों के लिए हलाल प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। इसकी पुष्टि भारत सरकार के व्यापार विभाग की अधिसूचना संख्या 2022-23/25 से की जा सकती है। इस अधिसूचना में कहा गया है कि हलाल प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, मगर जो प्राप्त करते हैं उनको रोकना संविधान की धाराओं के विरुद्ध है।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 नवंबर) के अनुसार जमीयत उलेमा के महासचिव ने यह दावा किया है कि केंद्र सरकार के उद्योग मंत्रालय ने ही कुछ संस्थाओं को हलाल प्रमाणपत्र जारी करने के लिए

अधिकृत किया है। हिंदुस्तान से दुनिया भर के देशों में भारी मात्रा में मांस और उसके उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। जो विदेशी कंपनियां इसे खरीदती हैं उनकी यह शर्त होती है कि जिस माल के ऊपर हलाल प्रमाणीकरण का लेबल लगा होगा हम वही माल खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार की नीति इस मामले में स्पष्ट है तो किसी भी राज्य सरकार को इस पर पाबंदी लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 नवंबर) के अनुसार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र भेजकर उनसे यह मांग की है कि बिहार में भी हलाल प्रमाणपत्र जारी करने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाए।

मुंबई उर्दू न्यूज (27 नवंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है, जिसमें मुसलमानों के कुछ पंजीकृत संगठनों द्वारा हलाल प्रमाणपत्र जारी करने को गैरकानूनी करार दिया गया है। बोर्ड के अनुसार राज्य सरकार का यह फैसला धार्मिक आजादी में हस्तक्षेप और देश के हितों के खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि इस्लाम ने अपने अनुयायियों के लिए खान-पान और रहन-सहन के कुछ नियम बनाए हुए हैं, जिनका पालन करना सभी मुसलमानों के लिए जरूरी है। इसमें कुछ चीजों को हराम बताया गया है और मुसलमानों को यह निर्देश दिया गया है कि वे इसका इस्तेमाल न करें। यह मामला सिर्फ मांस और उसके उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे कई अन्य उत्पाद भी होते हैं, जिनमें इन वस्तुओं का मिश्रण होता है और यह इस्लाम में हराम है। उन्होंने कहा कि हलाल प्रमाणीकरण का अर्थ यह है कि यह उत्पाद हलाल माने जाने वाले स्तर के अनुरूप है और इसमें किसी ऐसी वस्तु की मिलावट नहीं है, जिसे इस्लाम में हराम माना जाता है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार के इस फैसले से मुस्लिम देशों में निर्यात पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और इससे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी।

इत्तेमाद (20 नवंबर) ने अपने संपादकीय में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा हलाल प्रमाणित वस्तुओं पर लगाए गए प्रतिबंध की आलोचना करते हुए कहा है कि इस पाबंदी से एक बार फिर भाजपा और योगी की मुस्लिम दुश्मनी स्पष्ट हो गई है। यह पाबंदी उस समय लगाई गई जब लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि कुछ संगठन गैरकानूनी तौर पर हलाल प्रमाणपत्र जारी करके अनुचित मुनाफा कमा रहे हैं और इससे होने वाली आय का इस्तेमाल आतंकी संगठनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है। समाचारपत्र ने कहा है कि ये प्रमाणपत्र केंद्र सरकार की निगरानी में जारी किए जाते हैं और इनका लक्ष्य यह है कि उपभोक्ताओं को इस बात से अवगत कराया जाए कि इन उत्पादों में किसी ऐसी वस्तुओं की मिलावट नहीं है, जिसे इस्लाम में हराम माना जाता है। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि यह पाबंदी मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए जानबूझकर लगाई गई है। ■

लोकसभा के चुनाव में भाजपा को सशर्त समर्थन देने की घोषणा

मुंबई उर्दू न्यूज (17 नवंबर) के अनुसार बरेलवी संप्रदाय के प्रमुख एवं इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने बरेली शरीफ की दरगाह आला हजरत में स्थित अपने निवास स्थान पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में फिलिस्तीन की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी है। इस अवसर पर मौलाना ने कहा कि वे प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और वे 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को विजयी बनाने में भी सहायता करेंगे, मगर एक शर्त के साथ कि प्रधानमंत्री को यह ऐलान करना होगा कि वे इजरायल के बजाय फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। गौरतलब है कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध के दौरान भारत सरकार ने फिलिस्तीन को सहायता उपलब्ध कराई थी। भारत के इस कदम पर मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। मौलाना तौकीर ने कहा कि कल वे जुमे की नमाज को संबोधित करेंगे, जिसमें हिंदू मुसलमान सहित सभी संप्रदाय के लोग भारी संख्या में शामिल होंगे। पहले यह जनसभा इस्लामिया ग्राउंड में होनी थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। अब यह जनसभा नौमहला मस्जिद में होगी। मौलाना ने इस्लामिया ग्राउंड में जनसभा को आयोजित करने की अनुमति नहीं देने के लिए पुलिस व प्रशासन को अपना निशाना बनाया और कहा कि प्रशासन यह नहीं चाहता कि हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठें।

मौलाना ने कहा कि प्रशासन ने इस्लामिया ग्राउंड के बजाय नौमहला मस्जिद में जनसभा की अनुमति इसलिए दी है, ताकि मस्जिद का नाम सुनते ही हिंदू इसमें न आएं। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के जो लोग शांति चाहते हैं उनके लिए फिलिस्तीन के समर्थन में सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया गया है। इसमें फिलिस्तीन के लिए दुआ मांगी जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत सरकार ने फिलिस्तीन की अपनी पुरानी नीति का जिस तरह से समर्थन किया है, उसके लिए हम सरकार को बधाई देते हैं। मौलाना ने कहा कि अगर मोदी सरकार का इजरायल से कोई संबंध नहीं है तो वह उसे मान्यता देने से इंकार करके अपने राजदूत को वापस बुला ले। अगर मोदी सरकार ऐसा करती है तो हम भाजपा के साथ खड़े हैं और आगे भी चुनाव में उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि इजरायल के अत्याचारों के खिलाफ अमेरिका सहित सभी देशों में विरोध हो रहा है, लेकिन सऊदी अरब ने फिलिस्तीन के मामले में सही भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने कहा कि दुनिया के मुसलमानों को सऊदी अरब के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।

मुंबई उर्दू न्यूज (19 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि जब मौलाना तौकीर रजा खान के बयान पर लोगों की नजर पड़ी होगी तो उन्हें निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगा होगा,

लेकिन जब मौलाना की शर्त देखी होगी तो उन्हें शांति मिली होगी। खबर थी कि मौलाना ने फिलिस्तीनियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है और यह घोषणा की है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की मदद करने के लिए तैयार हैं। काफी लोगों ने यह भी सोचा होगा कि कुछ मुस्लिम विद्वानों की तरह मौलाना भी मोदी की गोद में तो नहीं बैठ गए। ऐसे लोगों को 'गोदी उलेमा' भी कहा जा सकता है। इस सूची में कौन-कौन है इसका जवाब पूरा देश जानता है, इसलिए यहां पर किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। खैर, मौलाना तौकीर रजा खान ने अपनी शर्त में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर वे प्रधानमंत्री मोदी की सराहना और भाजपा के समर्थन की बात कर रहे हैं तो आंखें बंद करके नहीं कर रहे हैं। उनके पास अपनी शर्त है और वे उसी स्थिति में भाजपा का समर्थन कर सकते हैं, जब मोदी सरकार इजरायल का साथ छोड़कर फिलिस्तीन के साथ खड़ी हो जाए।

समाचारपत्र का कहना है कि मौलाना को यह भी अंदाजा होगा कि मोदी सरकार उनकी इस शर्त को कभी नहीं मानेगी और मानेगी भी तो कैसे? यह सरकार तो पहले से ही 'वी स्टैंड विद इजरायल' का नारा लगा रही है। जब संयुक्त राष्ट्र में सही मायने में फिलिस्तीन का समर्थन करने का सवाल आता है तो भारत सरकार अमेरिका और इजरायल के साथ खड़ी नजर आती है। सिर्फ यह कह देने से कि हम फिलिस्तीनी रियासत की स्थापना के पक्ष में हैं या संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के समर्थन में पेश किए गए कुछ प्रस्तावों का समर्थन करके यह संकेत देना कि हम फिलिस्तीनियों का भला चाहते हैं, इससे मोदी सरकार अपने इजरायल समर्थक रवैये को छिपा नहीं सकती। खैर, यह दो देशों की विदेश नीति का मामला है और देश के प्रमुख यह भलीभांति जानते हैं कि देश के लिए बेहतर क्या है, लेकिन यह बात तो बिल्कुल साफ है कि हिंदुस्तान का झुकाव फिलिस्तीन की तरफ नहीं, बल्कि इजरायल की तरफ है।

कुछ लोग वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का हवाला देते हुए कहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के समर्थन में क्या भाषण दिया है। उनका यह कहना कि इजरायल-हमास युद्ध में नागरिकों का मारा जाना निंदनीय है। क्या यह काफी है? इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया जा सकता है कि उन्होंने इजरायल में होने वाली मौतों के साथ-साथ फिलिस्तीन में मरने वालों का उल्लेख तो किया है। बात मौलाना तौकीर रजा के बयान और शर्त से शुरू हुई थी और इस पर कुछ लोग नाक-भौं चढ़ा रहे हैं। हालांकि, मौलाना के इस बयान की सराहना की जानी चाहिए। कोई तो है जो यह जानते हुए भी कि सरकार में इजरायल समर्थकों का जोर है और राजनीतिक उद्देश्य से इस युद्ध को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया है। चुनावों तक में इसे एक मुद्दा बना दिया गया है। आखिर किसी ने यह कहने की हिम्मत तो की कि सरकार फिलिस्तीन के साथ खड़ी हो जाए तो वह भाजपा के समर्थन के लिए तैयार है।

समाचारपत्र का कहना है कि आज की राजनीति में शर्त का होना बहुत जरूरी है। मुसलमान काफी समय से बिना किसी मांग या शर्त के सिर्फ सेक्युलरिज्म के आधार पर अपने वोट देते चले आ रहे हैं, लेकिन मौलाना तौकीर रजा ने एक राह दिखाई है कि सरकार कोई भी हो उसके सामने शर्तें रखी जा सकती हैं। हालांकि, अन्य मुस्लिम विद्वान भी फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। यहां तक कि मौलाना अरशद मदनी ने तो हमास के पक्ष में भी आवाज बुलंद की है। इन सबका लक्ष्य सरकार को यह बताना है कि फिलिस्तीन की समस्या इस देश के मुसलमानों के लिए सर्वोपरि है, क्योंकि उनका संबंध उनकी आस्था और उनकी धार्मिक परंपराओं से है और

इस देश के नेताओं और शासकों को चाहिए कि वे उनकी भावनाओं की कद्र करें।

टिप्पणी: हालांकि, प्रारंभ से ही सूफियों और दरगाहों के समर्थन के प्रश्न पर भारतीय मुसलमानों के विभिन्न वर्गों में मतभेद रहे हैं। इस संप्रदाय में अल्लाह और इस्लामी पैगंबर हजरत मोहम्मद की निजी भक्ति और संतों की वंदना जैसे सूफी प्रथाओं के साथ-साथ शरीयत के साथ जुड़ाव पर भी जोर दिया गया है। इस संप्रदाय को नई शक्ति अहमद रजा खान के कारण मिली, जिन्होंने 1904 में मदरसा मंजर-ए-इस्लाम के साथ-साथ इस्लामी स्कूलों की भी स्थापना की। उनके अनुयायी अहले सुन्नत वल जमात कहे जाते हैं और उनकी गिनती सुन्नी मुसलमानों में होती है। बरेलवी संप्रदाय की देवबंदी संप्रदाय से दुश्मनी काफी पुरानी है। दोनों एक दूसरे को काफिर करार देते हुए पिछले दो सौ साल से फतवे जारी करते आ रहे हैं। देवबंदियों का संबंध वहाबी संप्रदाय से है और वे सूफियों को मानने और दरगाहों पर हाजिरी व चादरें चढ़ाने के सख्त खिलाफ हैं। देवबंदी इसे इस्लाम के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध मानते हैं। दोनों संप्रदायों में कुरान की परिभाषा पर भी काफी मतभेद है। खास बात यह है कि देवबंदी शुरू से ही अंग्रेजों के सख्त विरोधी रहे हैं। जबकि बरेलवियों ने अंग्रेजों का समर्थन करने से कभी परहेज नहीं किया है। इसके अतिरिक्त देवबंदी पाकिस्तान के विरोध में रहे हैं। जबकि बरेलवी संप्रदाय ने पाकिस्तान का जोरदार समर्थन किया था। बरेलवियों का दावा है कि भारत और पाकिस्तान में उनके समर्थकों की संख्या बीस करोड़ से भी अधिक है। खास बात यह है कि 1992 अयोध्या के विवादित ढांचे को गिराए जाने के बाद जब देश के मुसलमानों ने सरकार का विरोध शुरू किया था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने बरेलवी संप्रदाय का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया था और वे इस संदर्भ में बरेली में आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की दरगाह पर हाजिरी देने के लिए भी गए थे, मगर उनके सत्ता से बेदखल होने के बाद यह मामला ठप पड़ गया।

उर्दू मीडिया द्वारा संघ प्रमुख की आलोचना

उर्दू टाइम्स (26 नवंबर) का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक नया तर्क पेश किया है कि एक समय आएगा जब पूरी दुनिया सनातनी हो जाएगी। अर्थात सभी लोग सनातन धर्म को स्वीकार कर लेंगे। मोहन भागवत का यह दृष्टिकोण शेख चिल्ली के स्वप्न जैसा है, क्योंकि खुद भारत में भी सनातन धर्म तेजी से दम तोड़ रहा है। इसका अस्तित्व खतरे में है, जिसे बचाने के लिए कोई गंभीर कोशिश नहीं की जा रही है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए पूरी दुनिया सनातन धर्म को कैसे स्वीकार कर लेगी? जबकि इस्लाम का दावा है और इसमें सच्चाई भी है कि एक समय ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी, लेकिन ईमान वालों की संख्या कम होगी। पूरी दुनिया इसी ओर अग्रसर है। अमेरिका और यूरोप आदि देशों में लोग तेजी से इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, मोहन भागवत एक नया दावा पेश कर रहे हैं।

समाचारपत्र का कहना है कि ये वही मोहन भागवत हैं जो अब तक यह दावा कर रहे थे कि भारत में रहने वाले मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। जबकि उन्हें यह क्यों मालूम नहीं कि जब दुनिया बनी और इस धरती पर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम प्रकट हुए और उनकी बाई पसली से मां हव्वा पैदा हुई। ये दोनों मुसलमान थे। इसी से पूरी दुनिया के मनुष्य वजूद में आए और मुसलमानों का वंश ही पूरी दुनिया में फैला। फिर

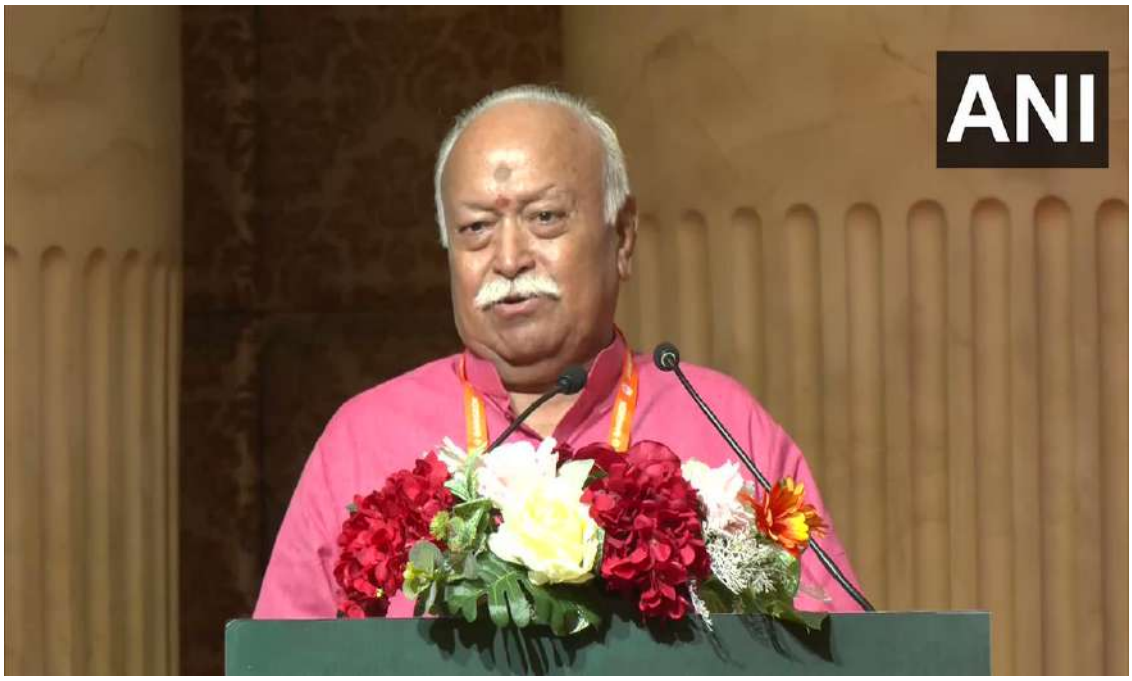

उन्होंने अपने-अपने पसंद के धर्मों को स्वीकार किया। मोहन भागवत भी यह जानते होंगे, मगर अनजान बनकर वे एक नया दावा पेश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया सनातनी हो जाएगी। यह उनका स्वप्न है। स्वप्न देखना कोई अपराध नहीं है, मगर शेख चिल्ली के स्वप्न हंसी के पात्र बन जाते हैं। आरएसएस की मानसिकता शुरू से ही मुस्लिम विरोधी रही है, क्योंकि उनका वजूद इसी आधार पर आया है। वे यह कभी नहीं चाहेंगे कि मुसलमान भारत में खुशहाल रहें, इसलिए वे नित नए शोशे छोड़ते रहते हैं। दुर्भाग्य से आज मोदी सरकार का रिमोर्ट कंट्रोल आरएसएस के हाथ में है। दिल्ली में आरएसएस के चिंतक जो कहते हैं, मोदी सरकार वही करती है।

समाचारपत्र का दावा है कि जितने भी मुस्लिम विरोधी व शरीयत के खिलाफ निर्णय होते हैं, उन सभी में शत-प्रतिशत आरएसएस का दखल होता है। चाहे वह तीन तलाक को खत्म करने की बात हो या कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने का फैसला। पिछले दस सालों में आरएसएस ने ठोस पैमाने पर काम किया है। उसने सबसे पहले महत्त्वपूर्ण पदों पर अपने खास लोगों को बैठाया और उसके बाद उन्होंने न्यायपालिका को भी प्रभावित करने का अभियान शुरू किया। न्यायाधीशों का चयन भी उन्हीं की इच्छा से हुआ। उच्च सरकारी नौकरियों के चयन बोर्ड में भी उन्हीं के लोग बैठाए गए, इसलिए कोई भी महत्त्वपूर्ण सरकारी पद पर मुसलमान नहीं है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम और मध्य प्रदेश को ही ले लीजिए। यहां के मंत्रालयों में कोई भी मुस्लिम उच्च अधिकारी नहीं है। उन्हें साइड पोस्टिंग पर लगा दिया गया है। जिन मुसलमानों का जमीर होता है वे घुटन महसूस करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं। इसी तरह से आईपीएस का भी मामला है।

समाचारपत्र ने यह खुलासा किया है कि महाराष्ट्र में एक अत्यंत बुद्धिमान आईपीएस अधिकारी अब्दुर रहमान को साइड पोस्टिंग पर रखकर उन्हें मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। हालांकि, उनके त्यागपत्र के समय हमने इसका विरोध करते हुए इसे कायरतापूर्ण हरकत बताया

था, क्योंकि अन्याय के खिलाफ युद्ध इसी व्यवस्था में रहकर लड़ा जा सकता है। अगर वहां से बाहर हो गए तो आम आदमी बन गए। फिर उन्हें कोई नहीं पूछता। कश्मीरी युवक शाह फैसल जो यूपीएससी की परीक्षा में टॉपर थे, उन्हें भी इसी तरह से घुटन का शिकार होकर त्यागपत्र देना पड़ा और उन्होंने एक अलग पार्टी बनाकर चुनाव भी लड़ा। हालांकि, वे विफल रहे। समाचारपत्र का कहना है कि भारत एक महान देश है और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस देश में शताब्दियों से विभिन्न धर्मों के अनुयायी आबाद हैं। इनका रंग, नस्ल, जबान और संस्कृति सब अलग-अलग है और इनमें कभी भी आपस में टकराव नहीं हुआ। जबसे राजनीति में मजहब का प्रभाव बढ़ा तब से इन राजनीतिक नेताओं ने मजहब को अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का जरिया बना लिया और तभी से देश में विघटन, बेचैनी, हिंसा, तनाव और मॉब लिंचिंग का सिलसिला शुरू हुआ। तभी से हर मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया गया और मस्जिदों की भूमि पर कब्जा करके वहां पर मंदिरों का निर्माण किया गया। इस पर भी मुसलमान चुप हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जब समय पलटेगा तो ये चारों खाने चित्त हो जाएंगे।

समाचारपत्र ने यह सुझाव दिया है कि पहले देश में जितने भी सनातनी हैं उन्हें ही एकजुट कर लें। यही बहुत बड़ी बात होगी। वे अन्य धर्मों का सम्मान करना तो सीखें। आरएसएस को मुसलमानों के प्रति नकारात्मक रवैया छोड़कर साकारात्मक फैसले करने चाहिए। जब तक उनकी सोच में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक उनका मिशन बार-बार फेल होता रहेगा और उसे कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मोहन भागवत को आमंत्रण है कि वे इस्लाम का गहराई से अध्ययन करें। उन्हें खुद ही यह अहसास हो जाएगा कि इस्लाम ही दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है जो इंसानियत का संदेश देता है और आपसी भाईचारे का प्रचार करता है। मोहन भागवत अगर इस्लाम को समझ लें तो वे भी इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे। इसलिए मोहन भागवत को स्वप्न देखना छोड़कर हकीकत की दुनिया में आना चाहिए।

उर्दू टाइम्स (16 नवंबर) में राम पुनियानी का एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसका शीर्षक है, "आरएसएस अंबेडकर की प्रशंसा करने पर मजबूर।" लेख में कहा गया है कि भाजपा और आरएसएस के नेता समय-समय पर अंबेडकर का नाम लेते हैं और यह दावा करने का प्रयास करते हैं कि वे अंबेडकर का सम्मान करते हैं और उनकी शिक्षाओं को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। हालांकि, हकीकत यह है कि डॉ. अंबेडकर और आरएसएस का दृष्टिकोण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। यह भी हकीकत है कि अंबेडकर हमेशा भारतीय समाज से जात-पात के नाम पर भेदभाव, पक्षपात एवं धर्मांधता का विरोध करने पर जोर देते रहे हैं। उनका प्रयास सामाजिक न्याय पर जोर देने का रहा है। इसके विपरीत आरएसएस हमेशा जात-पात की वर्ण व्यवस्था को बरकरार रखने के पक्ष में है। हद तो यह है कि इन दोनों में इस तरह के मतभेद के बावजूद आरएसएस के चिंतक विभिन्न रूपों में यह जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि वे अंबेडकर की शिक्षाओं के अनुयायी हैं। सावरकर 'द्विराष्ट्र सिद्धांत' के समर्थक थे और वे यह चाहते थे कि भारत को दो देशों हिंदू देश और मुस्लिम देश में बांट दिया जाए। संघ परिवार ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था, लेकिन राजनीतिक स्वार्थों के कारण अब संघ परिवार अंबेडकर का अनुयायी बन गया है।

रोजनामा सहारा (11 नवंबर) में साहिल जुबैरी का एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें कहा गया है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषणों और बयानों पर जिन लोगों की नजर रहती है वे यह जानते हैं कि मोहन भागवत की बोली के एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। वे शायद इस

बात में विश्वास करते हैं कि ऐसी बात कहिए जिसके सौ पहलू हों। उनका हर बयान पहले बयान के ठीक विपरीत होता है। कभी वे तमाम हिंदुस्तानियों को हिंदू बताते हैं और सबका डीएनए एक होने का दावा करते हैं। इससे साफ है कि संघ को भारत की बहुसंस्कृति पसंद नहीं है। वह देश के सभी फिरकों की प्राचीन पहचान, धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय पहचान को स्वीकार नहीं करती है। उसका इस बात पर जोर रहता है कि सभी हिंदुस्तानियों के लिए एक खास पहचान हिंदुत्व होना चाहिए। अब संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक नया शोशा छोड़ा है कि संघ न केवल भारत के सभी फिरकों को अनुशासन में लाने के लिए उन्हें शुद्ध करना चाहता है, बल्कि वह पूरी दुनिया को आर्य बनाकर उन्हें आर्यन संस्कृति के रंग में रंगना चाहता है।

लेखक का कहना है कि आजादी से पहले हिंदू महासभा और आर्य समाज ने मुसलमानों में शुद्धि का अभियान चलाया था, जिसका उद्देश्य था कि जिन मुसलमानों के पूर्वजों को मुस्लिम शासकों ने अपनी ताकत के बल पर मुसलमान बनाया है उनकी औलादों को वापस हिंदू धर्म में लाया जाए। अब सत्ता में आने के बाद भाजपा और आरएसएस ने भी घर वापसी का अभियान शुरू किया है और संप्रदायों को शुद्ध करने की बात की जा रही है। इसमें संघ कितना सफल होता है यह तो समय ही बताएगा। मोहन भागवत ने ये बातें 24 नवंबर को थाइलैंड के बैंकॉक में आयोजित तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस में कही हैं। इसके साथ ही उन्होंने आर्यन संस्कृति की बहस भी छेड़ दी है। मोहन भागवत की दृष्टि में आर्यन एक संस्कृति है और वे उसमें पूरी दुनिया को रंगने की इच्छा रखते हैं। अर्थात वे अपनी हिंदू संस्कृति के रंग में दुनिया को रंगना चाहते हैं। संघ जो भी इच्छा रखे उसे कार्यान्वित करने के लिए वह स्वतंत्र है। संघ अपनी स्थापना से लेकर आज तक इसी लक्ष्य पर काम करता आ रहा है। संघ का यह सौभाग्य है कि दुनिया में न सही, परंतु कम-से-कम भारत में उसकी इच्छा मोदी सरकार में जरूर सफल हो रही है, इसलिए अब मोहन भागवत पूरी दुनिया को आर्यन संस्कृति में रंगने की कोशिश कर रहे हैं।

समाचारपत्र का कहना है कि मोहन भागवत ने अपनी आदत और संघ की नीति के अनुसार अंग्रेजों के साथ-साथ मुसलमानों को भी नहीं बख्शा है और कहा है कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने भी हिंदुओं के प्रति आक्रामक रूख अपनाया था। इससे पहले मुसलमानों ने भी भारत पर कब्जा करके तबाही मचाई थी। तमाम फिरकों को शुद्ध करने का अर्थ तो यही है कि संघ सभी संप्रदायों और खास तौर पर मुसलमानों का शुद्धिकरण करके उनकी घर वापसी करवाना चाहता है। वह उन्हें अपने मनगढ़ंत हिंदू संस्कृति के रंग में रंगना चाहता है। 'जियो और जीने दो' यही हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत है, मगर संघ परिवार इस मंत्र में विश्वास नहीं रखता है। संघ के दूसरे प्रमुख माधव सदाशिव गोलवलकर ने अपनी पुस्तक 'बंच ऑफ थॉट्स' में देश के तीन बड़े दुश्मन बताए थे, जिनमें मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट शामिल हैं।

संघ आज भी इन तीनों को अपनी राह का कांटा मानता है और उनसे निपटने के लिए उसने अलग-अलग तरीके अपनाए हैं। हालांकि, उसने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का भी गठन किया है, मगर हमारी जानकारी के अनुसार भाजपा या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से संबंधित मुसलमानों के लिए संघ की शाखाओं के दरवाजे आज भी बंद हैं।

समाचारपत्र का दावा है कि आरएसएस किसी गैर-ब्राह्मण को अपना सरसंघचालक नहीं बनाता है। चाहे वह ऊची जाति का हिंदू ही क्यों न हो। रज्जू भैया को गैर-ब्राह्मण होने के कारण अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। संघ हिंदू धर्म की वर्ण-व्यवस्था में विश्वास रखता है। उसके अनुसार हिंदू धर्म में ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा स्थान है। वह धर्म के आधार पर खास तौर से मुसलमानों और ईसाइयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है। संघ तिरंगे झंडे का भी विरोध कर चुका है। भले ही संघ पूरी दुनिया को आर्यन संस्कृति में रंगने की बात करता है, मगर उसने अनजाने में भी गाजा में 15 हजार लोगों के कत्लेआम पर एक शब्द नहीं कहा। बैंकॉक में होने वाले इस त्रिदिवसीय सम्मेलन में गाजा में युद्धविराम की मांग तक नहीं की गई। हिंदू धर्म को मानने वाले दुनिया को कैसे हिंदू बनाएं इस सम्मेलन का यही एजेंडा है। ■

गैर–मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ कार्रवाई पर गतिरोध

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 14 हजार से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करने का जो प्रयास शुरू किया था वह शिक्षा विभाग और मदरसा शिक्षा बोर्ड के बीच उत्पन्न मतभेदों के कारण फिलहाल खटाई में पड़ गया है।

रोजनामा सहारा (18 नवंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर यह मांग की है कि गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को अन्य मदरसों के साथ मिलाने के कार्यक्रम को शीघ्र-अति-शीघ्र शुरू किया जाए, ताकि प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य 'सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास' का ठोस प्रदर्शन हो सके। इस पत्र में डॉ. जावेद ने लिखा है कि सरकार ने पिछले साल पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच करवाई थी और उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी। इसमें इस बात का खुलासा किया गया था कि 8449 मदरसे ऐसे हैं, जो मदरसा शिक्षा बोर्ड या अन्य संस्थान से संबंधित नहीं हैं। एक साल गुजर जाने के बावजूद इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन मदरसों में लगभग साढ़े सात लाख छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनमें से 90 प्रतिशत का संबंध

पिछड़े वर्ग से है। इन मदरसों को मान्यता न दिए जाने के कारण कुछ लोग इन मदरसों को गैरकानूनी भी कहने लगे हैं।

इस संबंध में ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस-ए-अरबिया ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री व अन्य अधिकारियों को भेजा था, जिसमें कहा गया था कि मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा पिछले आठ वर्षों से नए मदरसों को मान्यता नहीं दी जा रही है। हालांकि, उन्होंने अपने दस्तावेज बोर्ड में जमा करवा रखे हैं। अब उन्हें बंद करने और जुर्माना लगाने की भी धमकियां दी जा रही हैं। इसी समाचारपत्र ने एक अन्य समाचार में कहा है कि उत्तर प्रदेश में मदरसों को मान्यता देने की जिम्मेवारी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के तहत चलने वाले उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की है, मगर 2015 से किसी भी नए मदरसे को मान्यता नहीं दी जा रही है। जबकि ये मदरसे सरकार द्वारा तय शर्तों को पूरा करते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग का दावा है कि ये मदरसे उसके अंतर्गत हैं और मदरसा शिक्षा बोर्ड को इन्हें मान्यता देने का कोई अधिकार नहीं है। इन विभागों के आपसी विवाद के कारण अभी तक यह मामला खटाई में पड़ा हुआ है। समाचारपत्र ने यह आरोप लगाया है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा इन मदरसों को बंद करने और उन पर जुर्माना करने की धमकियां दी जा रही हैं।

इंकलाब (27 नवंबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश में मदरसों की मंजूरी का मामला खटाई में पड़ा हुआ है, क्योंकि इस संदर्भ में मदरसा शिक्षा बोर्ड और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में मतभेद हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह को इन मदरसों की मंजूरी के लिए एक पत्र भी लिखा था, लेकिन अभी तक उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली है। मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने इंकलाब के संवाददाता को बताया कि जो मदरसे गैर-मान्यता प्राप्त हैं उन्हें मंजूरी मिलनी चाहिए, मगर कुछ अधिकारी इसमें बाधक बने हुए हैं। वे कभी पोर्टल की तैयारी का बहाना बनाते हैं तो कभी ऑनलाइन आवेदन की आड़ लेते हैं और कभी सर्वे करवाकर डाटा इकट्ठा करने की बात कहकर टाल देते हैं।

सियासत (19 नवंबर) ने अपने संपादकीय में मदरसों के बारे में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान की निंदा की है और कहा है कि मुख्यमंत्री निरंतर मुसलमानों को अपना निशाना बना रहे हैं। वे कभी मस्जिदों और मदरसों

को निशाना बनाते हैं तो कभी किसी के खान-पान पर टिप्पणी करते हैं। ऐसा लगता है कि असम के मुख्यमंत्री सांप्रदायिकता का जहर उगलने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पीछे छोड़ना चाहते हैं। समाचारपत्र का कहना है कि अपनी सरकार की विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए वे इस तरह के विवाद उत्पन्न करते हैं। उनके इन बयानों से समाज में काफी बेचैनी है, मगर मुख्यमंत्री इसकी परवाह करने के लिए तैयार नहीं हैं। हैरानी की बात यह है कि भाजपा हाईकमान ने भी उन्हें ऐसे विवादित बयान देने से नहीं रोका है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों को भी बंद करने की धमकी दी है। समाचारपत्र का कहना है कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार पद पर हैं और उन्हें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं है। उनका यह बयान भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है।

एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में रामायण–महाभारत को शामिल करने की सिफारिश

रोजनामा सहारा (22 नवंबर) के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की एक उच्चस्तरीय कमेटी ने यह सिफारिश की है कि महाकाव्य रामायण और महाभारत को एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया जाए। कमेटी ने यह सुझाव दिया है कि इन महाकाव्यों को इतिहास पाठ्यक्रम के तहत भारत के शास्त्रीय काल के ग्रंथों की श्रेणी में रखा जा सकता है। हालांकि, अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि रामायण और महाभारत के किस अध्याय को किस कक्षा में पढ़ाया जाएगा। इस उच्चस्तरीय कमेटी के अध्यक्ष प्रो. सीआई इसाक ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि कमेटी के पैनल ने यह भी सिफारिश की है कि संविधान

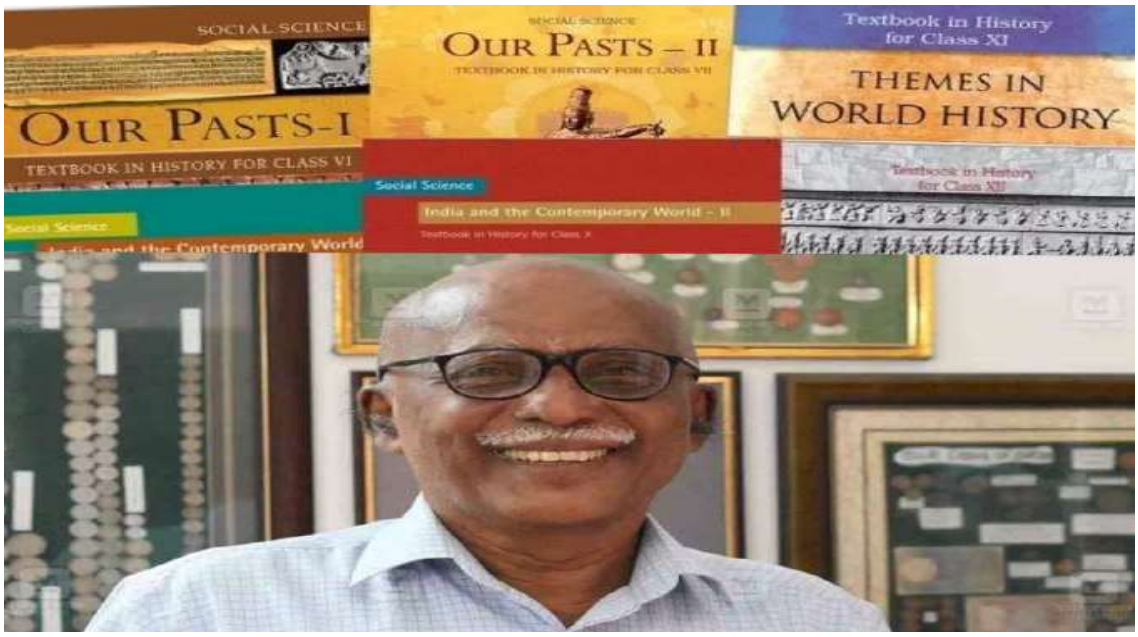

की प्रस्तावना को स्कूलों की सभी कक्षा की दीवारों पर लिखा जाना चाहिए और यह विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी होनी चाहिए। प्रो. इसाक इतिहास के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं। वे एनसीईआरटी के सोशल साइंस पाठ्यक्रम पर पुनर्विचार के लिए बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष हैं।

कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में भारतीय ज्ञान प्रणाली, वेदों और आयुर्वेद को भी शामिल किया जाए। कमेटी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों में इंडिया के बजाय भारत लिखा जाए। हालांकि, अभी एनसीईआरटी ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। प्रो. इसाक ने कहा कि हमने इतिहास को चार अवधियों शास्त्रीय काल, मध्यकालीन काल, ब्रिटिश युग और आधुनिक भारत में विभाजित करने का सुझाव दिया है। अभी तक देश में इतिहास को सिर्फ तीन अवधियों प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में पढ़ाया जाता है। अब हमने शास्त्रीय काल में महाकाव्य रामायण और महाभारत को भी पढ़ाने का सुझाव दिया है, ताकि छात्रों को यह मालूम हो कि राम कौन थे और उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी। इसी तरह से महाभारत के पात्रों और उनकी भूमिका के बारे में भी छात्रों को ज्ञान दिया जाना चाहिए।

रोजनामा सहारा (26 नवंबर) के अनुसार संभल के विवादित सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों में रामायण और महाभारत को शामिल करने का विरोध किया है और इस फैसले को भारत की परंपरा और धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध बताया है। उन्होंने कहा है कि रामायण और महाभारत को पाठ्यपुस्तकों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह कुरान शरीफ से बड़ी किताब नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर रामायण और महाभारत को धार्मिक आधार पर शामिल किया जा रहा है तो कुरान शरीफ को भी पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कुरान से महान कोई पुस्तक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकों को शामिल किया जाता है तो अन्य धर्मों की पुस्तकों को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। इससे देश में सांस्कृतिक एकता और देशभक्ति की भावना में बढ़ोतरी होगी।

विश्व

बांग्लादेश में विपक्ष के 139 प्रमुख नेताओं को सजा

रोजनामा सहारा (18 नवंबर) के अनुसार बांग्लादेश में आम चुनावों की घोषणा कर दी गई है। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त काजी हबीबुल अवल ने घोषणा की है कि बांग्लादेशी संसद के नए सांसदों को चुनने के लिए देश भर में सात जनवरी को मतदान होगा। उन्होंने कहा कि हम स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए कटिबद्ध हैं। गौरतलब है कि इससे पहले साल 2018 में बांग्लादेश में आम चुनाव हुए थे। इस चुनाव का विपक्ष ने बहिष्कार किया था और शेख हसीना की पार्टी ने एक पक्षीय सफलता प्राप्त की थी। इस बार भी मुख्य मुकाबला शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग और खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के बीच होगा। इस चुनाव पर विश्व के अनेक देशों की नजरें लगी हुई हैं।

इंकलाब (22 नवंबर) के अनुसार देश में चुनावों की घोषणा होते ही सरकार ने विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। हाल ही में विपक्ष के 139 प्रमुख नेताओं को विभिन्न आरोपों में कैद की सजा सुनाई गई है। विदेशी मीडिया के अनुसार बांग्लादेश के विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना पर यह आरोप लगाया है कि आने वाले चुनावों में वह फिर से धांधली कर सकती हैं। विपक्षी दलों ने यह मांग की है कि शेख हसीना को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए और एक राष्ट्रीय सरकार की निगरानी में निष्पक्ष चुनाव कराया जाना चाहिए। इसके साथ ही देश भर में सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सजा पाने वालों में प्रमुख विपक्षी दल बीएनपी के अनेक प्रमुख नेता शामिल हैं। उन पर विरोध प्रदर्शनों में हिंसा भड़काने और पुलिस पर हमला करने के आरोप लगाए गए थे। अब उन्हें चार महीने से लेकर साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई है। ये मुकदमे 2013 से लेकर 2018 के बीच तब दर्ज किए गए थे, जब विपक्ष ने हड़ताल और नाकेबंदी की थी। सजा पाने वालों में बीएनपी के

युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुल्तान सलाहुद्दीन टुकू और दो प्रमुख छात्र नेता शामिल हैं।

इंकलाब (20 नवंबर) के अनुसार बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय ने देश की सबसे बड़ी इस्लामी कट्टरपंथी पार्टी जमात-ए-इस्लामी के चुनाव में भाग लेने पर रोक लगा दी है। जमात-ए-इस्लामी के वकील ने बताया कि सरकार ने जमात-ए-इस्लामी पर देश विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के आरोप में प्रतिबंध लगाया था। इस प्रतिबंध को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन ने खारिज कर दिया। वहीं, पार्टी के प्रवक्ता मतीउर रहमान ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश में जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, मगर उसके कार्यकर्ताओं को चुनाव में भाग लेने से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीएनपी ने देशव्यापी हड़ताल का जो सिलसिला शुरू किया है, उसमें जमात-ए-इस्लामी भी भाग लेगी। प्रदर्शनकारी यह मांग कर रहे हैं कि आम चुनाव राष्ट्रीय सरकार की निगरानी में करवाए जाएं। गौरतलब है कि जमात-ए-इस्लामी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियों में शामिल है और उस पर 2013 से चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (19 नवंबर) के अनुसार बांग्लादेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच रस्साकशी चल रही है। देश में पिछले एक महीने से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरी ओर, बांग्लादेश के सबसे बड़े उद्योग कपड़ा उद्योग के साढ़े तीन हजार फैक्ट्रियों में काम करने वाले 40 लाख से अधिक मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दिया है। इनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। ये मजदूर देश में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए अपने वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश पिछले दो दशक से आर्थिक मंदी का शिकार है और इससे उबरने के लिए वह न केवल आर्थिक और व्यापारिक, बल्कि रक्षा संबंधी मामलों में भी चीन के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना लंबे समय से प्रधानमंत्री के पद पर हैं। वह किसी भी तरह से इस चुनाव को जीतना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने विपक्षी पार्टियों और मीडिया को कुचलने का अभियान छेड़ रखा है। बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया काफी समय से भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद हैं। जबकि एक अन्य विपक्षी पार्टी जमात-ए-इस्लामी पर सरकार ने चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हड़ताली मजदूरों की मांग है कि उनके वेतन में तीन गुना वृद्धि की जाए। वर्तमान आर्थिक संकट को देखते हुए कपड़ा उद्योग के मालिक मजदूरों की इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यही कारण है कि ये मजदूर अब हिंसा पर उतर आए हैं। हाल ही में उन्होंने 600 से अधिक कारखानों को आग के हवाले कर दिया है। ■

नीदरलैंड के चुनाव में इस्लाम विरोधी नेता को भारी सफलता

रोजनामा सहारा (24 नवंबर) के अनुसार हाल ही में नीदरलैंड में हुए चुनाव में इस्लाम विरोधी गीर्ट विल्डर्स की पार्टी 'पार्टी फॉर फ्रीडम' को भारी जीत प्राप्त हुई है। 150 सदस्यीय संसद में उनकी पार्टी को 37 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई है। जबकि वामपंथी दलों का गठबंधन उनसे काफी पीछे रह गया है। गौरतलब है कि विल्डर्स ने भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने और नूपुर शर्मा द्वारा रसूल के बारे में दिए गए बयान का डटकर समर्थन किया था। विल्डर्स 1963 में नीदरलैंड के नगर वेनलो में पैदा हुए थे। उनका संबंध रोमन कैथोलिक संप्रदाय से है, लेकिन वे स्वयं को नास्तिक मानते हैं। वे काफी समय से कुरान पर प्रतिबंध लगाने और नीदरलैंड में रहने वाले मुसलमानों को देश से निकालने का अभियान चला रहे हैं।

विल्डर्स की कट्टरपंथी सोच के कारण नीदरलैंड के तीन राजनीतिक दलों ने चुनावों में उनके साथ समझौता करने से मना कर दिया था। यूरोपीय यूनियन के पूर्व आयुक्त फ्रैंस टिमरमैन्स के नेतृत्व वाले वामपंथी दलों के गठबंधन को 25 सीटें प्राप्त हुई हैं। टिमरमैन्स ने कहा है कि नीदरलैंड में रहने वाले सभी लोग बराबर हैं और हम नीदरलैंड से किसी के भी निकाले जाने को सहन नहीं करेंगे। इन चुनावों में तीसरा स्थान तुर्किये मूल की मुस्लिम महिला दिलन येसिल्गोज की पार्टी ने हासिल की है। उनकी पार्टी ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की है। जबकि 20 सीटों के साथ पीटर ओमटजिगट की पार्टी चौथे स्थान पर है।

उर्दू टाइम्स (25 नवंबर) के अनुसार कट्टर मुस्लिम विरोधी गीर्ट विल्डर्स की पार्टी ने संसद की 150 सीटों में से 37 सीटें प्राप्त की हैं। बीबीसी का कहना है कि विल्डर्स की पार्टी की जीत से डच राजनीति में भूचाल आ गया है। इसका प्रभाव यूरोप की राजनीति पर भी पड़ेगा, जहां के विभिन्न देशों में इस्लाम विरोधी तत्व सक्रिय हैं। उन्हें इससे नया जीवन मिलेगा। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में विल्डर्स की पार्टी को सिर्फ 17 सीटें ही प्राप्त हुई थीं। सरकार बनाने के लिए विल्डर्स को अन्य दलों से गठबंधन करना होगा, क्योंकि 150 सदस्यीय संसद में बहुमत के लिए 76 सीटों की जरूरत होगी।

इत्तेमाद (27 नवंबर) ने अपने संपादकीय में नीदरलैंड के चुनावों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि दुनिया में जिस तरह से इस्लाम विरोधी तत्व

सक्रिय हो रहे हैं और इस्लाम विरोध को सत्ता पर पहुंचने का माध्यम बनाया जा रहा है, वह बेहद चिंताजनक है। अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर तबाही का बहाना बनाते हुए कई मुस्लिम देशों को युद्ध के मैदान में धकेल दिया था। फिर अरब बहार के नाम पर सत्ता में आए इस्लाम परस्त नेताओं का तख्ता पलट दिया गया और उसकी जगह अमेरिका ने अपनी कठपुतलियों को सत्ता में बैठा दिया। यूरोप में इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है, उसके कारण वहां पर मुसलमानों का जीना दूभर हो रहा है। कुरान को सरेआम जलाया जा रहा है और पैगंबर को आलोचना का निशाना बनाया जा रहा है। नीदरलैंड के इन चुनावों में जिस तरह से गीर्ट विल्डर्स को सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई हैं, वह मुसलमानों और इस्लाम के लिए गंभीर खतरे का संकेत है।

यहां तक कि फ्रांस में इस्लाम विरोधी भावनाओं को भड़काया जा रहा है। वहां मस्जिदों और इस्लामी स्कूलों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। इस तरह से इस्लाम विरोधी तत्व मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोलकर सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। विल्डर्स को नीदरलैंड का डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता है। उनका रूख इस्लाम के प्रति बेहद आक्रामक है, जिसके कारण 2004 से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती रही हैं। ब्रिटिश सरकार ने उनके ब्रिटेन में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था, मगर अदालत ने इस फैसले को अवैध घोषित कर दिया। हाल ही में विल्डर्स की पार्टी ने जो घोषणापत्र जारी किया था उसमें कहा गया था कि नीदरलैंड एक इस्लामी देश नहीं है और यहां पर मदरसे, कुरान और इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें यह भी घोषणा की गई थी कि जिन देशों में शरई कानून लागू हैं उनके साथ राजनयिक संबंध समाप्त कर लिए जाएंगे। खास बात यह है कि विश्व में ऐसे कई देश हैं जो इस्लाम के खिलाफ माहौल बनाकर सत्ता को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। इस तरह के हालात मुसलमानों और उलेमा के लिए बेहद चिंताजनक है। समाचारपत्र ने अपील की है कि दुनिया भर के मुसलमानों को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए।

भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकालने की मांग

रोजनामा सहारा (19 नवंबर) के अनुसार मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भारत के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से मांग की है कि मालदीव में जो भारतीय सैनिक मौजूद हैं उन्हें वहां से फौरन हटाया जाए। यह जानकारी राष्ट्रपति के कार्यालय ने दी है। गौरतलब है कि लगभग 75 भारतीय सैनिक मालदीव में तैनात हैं, जो समुद्री जहाज और रडार द्वारा मालदीव के विशेष आर्थिक जोन आदि की रक्षा करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि मालदीव में हमें विदेशी सैनिक स्वीकार नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि हम पड़ोसी देशों और अन्य

देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन पर्यटन, उद्योगों के विकास व प्रबंधन पर विशेष ध्यान देगा।

रोजनामा सहारा (16 नवंबर) के अनुसार नए राष्ट्रपति ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निमंत्रण दिया था, मगर उनकी व्यस्तता के कारण केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को मालदीव भेजा गया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री को मालदीव भेजा जाना इस बात का सबूत है कि भारत दोनों देशों की जनता के बीच सहयोग की भावना को बढ़ाने में विश्वास रखता है। मालदीव भारत का एक महत्त्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी देश है और हिंद महासागर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विजन सागर' और 'पड़ोसी प्रथम' की नीति में विशेष स्थान रखता है।

गौरतलब है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को चीन समर्थक माना जाता है। हालांकि, उन्होंने कहा है कि अगर भारत अपने सैनिकों को मालदीव से वापस बुलाता है तो उनकी जगह पर चीनी सैनिकों को तैनात नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मालदीव राजनीतिक होड़ में हिस्सा लेने के लिए भौगोलिक दृष्टि से बहुत छोटा देश है, इसलिए मैं इसमें मालदीव की विदेश नीति को शामिल नहीं करना चाहता। समाचारपत्र के अनुसार सितंबर महीने में होने वाले चुनावों में भाग लेते हुए मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव में भारत के वर्चस्व के खिलाफ अपना अभियान चलाया था।

रोजनामा सहारा (26 नवंबर) के अनुसार मालदीव में हुए हाल के चुनावों में मोहम्मद मुइज्जू सत्ता में आए हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने देश से भारतीय सैनिकों की मौजूदगी को समाप्त करने के लिए तीव्र गति से प्रयास कर रहे हैं और अपने पद की शपथ लेते ही मुइज्जू ने भारत सरकार से इस बात का अनुरोध किया है कि वह अपने सैनिक दस्ते को मालदीव से वापस बुला ले। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो-पैसिफिक स्टडीज के प्रमुख चिंतामणि महापात्रा के अनुसार मालदीव के नए राष्ट्रपति का यह फैसला न केवल भारत, बल्कि क्वाड देशों के लिए भी एक धक्का है। ये देश यह चाहते थे कि मालदीव इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बरकरार रखने के प्रयासों में भाग ले।

गौरतलब है कि मालदीव का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ मालदीव है। यह देश सैकड़ों द्वीपों के समूह से बना है। इसके अधिकांश द्वीप वीरान हैं। मालदीव भारत के लक्षद्वीप के दक्षिण में लगभग 700 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके कुल द्वीपों की संख्या 1192 है, मगर इनमें से सिर्फ 200 द्वीपों पर ही आबादी रहती है। मालदीव की राजधानी माले है। यहां पर देश की कुल आबादी के 80 प्रतिशत लोग निवास करते हैं। यहां रहने वाले 99 प्रतिशत से भी अधिक लोग मुसलमान हैं। मालदीव का तमिल में अर्थ होता है पहाड़ी द्वीप। विश्लेषकों का कहना है कि मालदीव

शब्द संस्कृत के शब्द मालाद्वीप पर आधारित है, जिसका अर्थ है द्वीपों की माला। जबकि कुछ अन्य विशेषज्ञ इसे अरबी भाषा का शब्द बताते हैं। यहां पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली है और उनकी सहायता के लिए संसद है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे तौर पर देश की जनता करती है।

समाचारपत्र का कहना है कि नए राष्ट्रपति के प्रशासन ने कहा है कि नई सरकार ने मालदीव और भारत के साथ हुए 100 से अधिक संधियों पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है, जिनमें से कुछ का संबंध सुरक्षा से है। विश्लेषकों का कहना है कि काफी समय से चीन इस द्वीप समूह में अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करता आ रहा था। कुछ वर्ष पहले चीन ने वहां के कुछ द्वीपों में अपने नौसैनिक अड्डे स्थापित करने का भी प्रयास किया था, मगर भारत की रणनीति के कारण उसे उसमें सफलता नहीं मिली।

उल्लेखनीय है कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्म सोलिह भारत के मित्र माने जाते हैं और उन्होंने 'इंडिया फर्स्ट' नीति का अनुसरण किया था। जबकि वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने 'इंडिया आउट' नीति के तहत अपना चुनावी अभियान चलाया था और उन्होंने मालदीव में भारत के सैनिक दस्ते की मौजूदगी को मालदीव की संप्रभुता के लिए खतरा करार दिया था। गौरतलब है कि वर्तमान राष्ट्रपति ने जिस भारतीय सैन्य दस्ते को मालदीव से बाहर निकालने की मांग की है उसमें हेलीकॉप्टर व हवाई जहाज चलाने वाले पायलट और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। ये लोग मालदीव के समुद्र में निगरानी और बचाव की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं।

एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न आस्ट्रेलिया के रिसर्च फेलो और मालदीव के जानकार अजीम जहीर का कहना है कि जिस तरह से मालदीव में भारतीय सैन्य दस्ते की मौजूदगी को चुनावी अभियान में उछाला गया था, उससे वहां की जनता प्रभावित हुई है। चीन 2013 से लेकर 2018 तक मालदीव में काफी सक्रिय रहा है। चीन ने वहां पर कई निर्माण परियोजनाएं की भी शुरुआत की है। चीन मालदीव में 200 मिलियन डॉलर की लागत से एक पुल का निर्माण कर रहा है, जो उसे माले के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्टडीज एंड फॉरेन पॉलिसी विभाग के उपाध्यक्ष हर्ष वी. पंत का कहना है कि क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में विश्व की बड़ी शक्तियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं, इसलिए मालदीव का भी महत्व काफी बढ़ गया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान और चीन काफी समय से मालदीव में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। एक दशक पूर्व पाकिस्तान ने मुस्लिम उलेमा के एक समूह को मालदीव के निवासियों को इस्लाम की शिक्षा देने के लिए भेजा था। गौरतलब है कि इससे पहले भी मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और चीन के प्रबल समर्थक अब्दुल्ला यामीन ने चुनाव में सफलता प्राप्त की थी, मगर वहां की जनता ने विद्रोह करके उनकी सरकार का तख्ता पलट दिया था। इसके बाद भारत समर्थक इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के सत्ता में आने के बाद भारत के साथ मालदीव के संबंधों में सुधार हुआ था। जहां तक मोहम्मद मुइज्जू का संबंध है, जब वे विपक्षी नेता थे तब से वे मालदीव की भारत के साथ दोस्ती का विरोध करते रहे हैं। इस समय मालदीव के व्यापारिक संबंध मुख्य रूप से भारत के साथ हैं। नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद अब चीन ने भी मालदीव में पूंजी निवेश करना शुरू किया है।

अमेरिका द्वारा आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों पर प्रतिबंध

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (19 नवंबर) के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कताइब सैयद अल-शुहादा ब्रिगेड और उसके महासचिव जरनल हाशिम फिनयान रहीम अल-सराजी को वैश्विक आतंकी घोषित करते हुए उन्हें 'काली सूची' में डाल दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय गठबंधन द्वारा इराक और सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस को खत्म करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उसमें पलीता लगाकर सैयद अल-शुहादा ब्रिगेड और उससे जुड़े कैडर ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा घोषित नई 'काली सूची' में ईरान समर्थक हिजबुल्लाह से संबंधित छह लोगों को शामिल किया गया है। ईरान ने सिपाह-ए-पासदारान-ए-इंकलाब-ए-इस्लामी और उसकी विदेशी ऑपरेशन फोर्स कुद्स फोर्स के जरिए हिजबुल्लाह से जुड़े हुए मिलिशिया समूहों को वित्तीय सहायता और आधुनिक हथियार उपलब्ध करवाने में विशेष भूमिका निभाई है। पेंटागन के अनुसार हाल ही में इन आतंकी संगठनों ने सीरिया और इराक में अमेरिकी सेना पर हमले किए थे। अक्टूबर के मध्य में ईरान से जुड़े हुए इन आतंकी संगठनों ने इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर साठ से अधिक हमले किए हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (16 नवंबर) के अनुसार अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने हमास और इस्लामिक जिहाद से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों और उनसे जुड़े समूहों पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया है कि ईरान हमास और इस्लामिक जिहाद को सैन्य सहायता व प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करता है। अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी महमूद खालिद जहर पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं, हमास से जुड़े हुए एक अन्य व्यक्ति मुअद इब्राहिम मोहम्मद रशीद अल-अतिली पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका का यह आरोप है कि अल-अतिली हमास और उससे जुड़े हुए संगठनों के लिए काम करता है। इसके अतिरिक्त इस्लामी आतंकी संगठनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के आरोप में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के सैन्य विंग के कमांडर नासिर अबू शरीफ और मुहजात अलकुद्स फाउंडेशन के उच्चाधिकारी जमील युसूफ अहमद अलियान पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

समाचारपत्र का कहना है कि दमिश्क में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के उप-महासचिव और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के सशस्त्र विंग अल-कुद्स ब्रिगेड के सेनापति अकरम अल-अजौरी को भी काली सूची में डाला गया है। अल-अजौरी पर आरोप लगाया गया है कि उसने गाजा, सीरिया, सूडान, लेबनान और यमन में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कैडर के लिए सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था की और उसमें कैडर को भर्ती भी किया। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के एक अन्य बयान के अनुसार हमास लेबनान में

स्थापित नबील चौमन एंड कंपनी को ईरान से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करता है और इस कंपनी के द्वारा सैकड़ों मिलियन डॉलर हमास को प्राप्त हुए हैं। इस धन हस्तांतरण के लिए चौमन के मालिक नबील खालिद हलील चौमन ने अपने बेटे खालिद चौमन और लेबनान स्थित एक अन्य मनी एक्सचेंजर रेडा अली खामिस के साथ मिलकर हमीद अहमद अल-खुदारी के साथ काम किया। इस कंपनी ने गाजा में इस्लामिक जिहाद को ईरान से प्राप्त आर्थिक सहायता को उपलब्ध कराने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। हाल ही में ईरान ने हमास को सात मिलियन डॉलर की धनराशि भी भेजी है।

इंकलाब (19 नवंबर) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में रहने वाले हमास समर्थकों के खिलाफ अमेरिकी प्रशासन कठोर कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति कार्यालय का कहना है कि हमास एक विदेशी आतंकी संगठन है, इसलिए अमेरिका में रहने वाले हमास समर्थक छात्रों के वीजा भी रद्द किए जा रहे हैं और उन्हें अमेरिका से निष्कासित किया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार से यह अनुरोध किया था कि वह अमेरिका में फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले लोगों और छात्रों की वीजा को रद्द करके उन्हें अमेरिका से निष्कासित करे।

पाकिस्तान ने अफगान माल को भेजने पर लगाई रोक

इंकलाब (16 नवंबर) के अनुसार अफगानिस्तान के वाणिज्य और उद्योग मंत्री नूरुद्दीन अजीजी ने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान द्वारा विदेशों से मंगाए गए अरबों रुपये के माल से भरे हजारों कंटेनरों को पाकिस्तान ने कराची बंदरगाह पर अवैध रूप से रोक रखा है। उन्होंने पाकिस्तान से यह मांग की कि इस माल को फौरन अफगानिस्तान भेजने की अनुमति दी जाए। पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी प्रशासन ने यह दावा किया है कि अफगानिस्तान ने अवैध रूप से इस माल को मंगवाया है। इससे पाकिस्तान को करों के रूप में लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान इस माल को तस्करी करके पाकिस्तान में भेजता है। अफगान प्रशासन ने इस बात की आलोचना की है कि पाकिस्तान विदेशों से मंगवाए गए माल को जानबूझकर अफगानिस्तान भेजने में रूकावट डाल रहा है। वह अवैध रूप से अधिक करों और ड्यूटी की रकम की भुगतान की आड़ लेकर अफगानिस्तान द्वारा मंगवाए गए तीन हजार से अधिक कंटेनरों को कराची बंदरगाह में रोके हुए है, जिससे अफगानिस्तान के व्यापारियों को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। इन कंटेनरों में उच्चकोटि के इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनी पुर्जे और कपड़े शामिल हैं। पाकिस्तान का कहना है कि जब से तालिबान अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ हुए हैं वे शुल्क मुक्त माल पहले की तुलना में कई गुना

अधिक मंगा रहे हैं, जोकि समझौते का खुला उल्लंघन है। इस्लामाबाद स्थित अफगानिस्तान दूतावास द्वारा जारी एक बयान में दावा किया गया है कि हाल ही में तालिबान के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हाजी नूरुद्दीन अजीजी ने इस संबंध में इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात की थी और उन्होंने शिकायत की थी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान द्वारा मंगवाए गए सैंकड़ों कंटेनरों को पिछले एक साल से अवैध रूप से कराची बंदरगाह पर रोक रखा है, जिससे अफगानिस्तान को अरबों रुपये का नुकसान हो रहा है।

हमारा समाज (22 नवंबर) के अनुसार इसकी जवाबी कार्रवाई के रूप में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से लगने वाली चमन सीमा को बंद कर दिया है। इससे पूर्व अफगास्तिान तोरखम सीमा को भी बंद कर चुका है। इसके कारण पाकिस्तानी व्यापारियों को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्वेटा की हजारा सब्जी मार्केट में फलों के व्यापारी हाजी अब्दुल्ला ने बताया कि फलों के सैकड़ों व्यापारियों ने अफगानिस्तान के सूबा कंधार में अनारों के बागों के मालिकों को कई महीने पहले करोड़ों रुपये अदा किए थे, ताकि फसल तैयार होने पर उनसे माल हासिल किया जा सके। अब अनारों की फसल तैयार हो गई हैं तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से लगने वाली सीमा को बंद कर दिया है, जिसके कारण पूरा व्यापार ठप हो गया है। क्वेटा के साथ-साथ कराची, सिंध और पंजाब की मंडियों में अनार और अंगूरों के दामों में 100 से 200 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के इशारे पर कुछ कबाइली संगठन पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर धरना दे रहे हैं। अब क्वेटा, चमन और कंधार से मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय मार्ग को भी बंद कर दिया गया है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच का व्यापार ठप हो गया है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (21 नवंबर) के अनुसार पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान सरकार प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकियों को पाकिस्तान के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों के संचालन के लिए किया जा रहा है। उन्होंने धमकी दी कि अगर अफगान सरकार ने इस संगठन से जुड़े हुए आतंकियों को हमारे हवाले नहीं किया तो हम इस संबंध में खुद सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि तालिबान के नेता यह अच्छी तरह से जानते हैं कि टीटीपी वाले कहां पर छिपे हुए हैं और वे कहां से पाकिस्तान में होने वाले आतंकी हमलों का संचालन करते हैं। हम इस बात को कतई सहन नहीं करेंगे कि अफगानिस्तान की भूमि से पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों का संचालन हो और अफगानिस्तान के शासक तमाशा देखते रहें। उन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि टीटीपी वाले पाकिस्तान पर हमला करें और हम मूकदर्शक बनके इस हिंसा को देखते रहें। आखिर हम उन्हें जवाब क्यों नहीं दें? जब तक इस प्रतिबंधित संगठन के आतंकी अपने शस्त्र हमारे हवाले नहीं करेंगे उनके खिलाफ हमारा अभियान जारी रहेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका ने हम पर यह दबाव डाला है कि हम पाकिस्तान में अवैध रूप से रहने वाले अफगान नागरिकों के निष्कासन की कार्रवाई को तुरंत रोक दें, मगर हम अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे।

हमारा समाज (23 नवंबर) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान द्वारा अफगान शरणार्थियों को जबरन अफगानिस्तान में धकेलने के प्रयासों की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि पाकिस्तान को इस तरह की कार्रवाई से बाज आना चाहिए।

सऊदी अरब द्वारा गाजा में पूर्ण युद्धविराम की मांग

इंकलाब (11 नवंबर) के अनुसार सऊदी अरब के मंत्रिमंडल ने एक बार फिर से गाजा में स्थाई युद्धविराम लागू करने की मांग की है। मंत्रिमंडल ने कहा है कि इस क्षेत्र में स्थाई स्थिरता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि आजाद फिलिस्तीनी रियासत की स्थापना की जाए। गौरतलब है कि सऊदी अरब सहित बहुत से देश यह चाहते हैं कि वर्तमान संकट को टालने के लिए स्थाई युद्धविराम होना जरूरी है ताकि युद्ध को अन्य क्षेत्रों में फैलने से रोका जा सके। इस अधिवेशन में पांचवें अरब सम्मेलन के परिणामों पर भी विचार किया गया, जिसमें यह कहा गया था कि इस क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पानी की समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाना जरूरी है। इसके साथ ही जल संकट को टालने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन को स्थापित करने की भी मांग की गई थी। सऊदी अरब ने यह आशा व्यक्त की है कि सभी देश इस बात का प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र में स्थाई शांति के समझौते को लागू किया जाए।

इंकलाब (29 नवंबर) के अनुसार मिस्र के विदेश मंत्री सामेह शौकरी ने कहा है कि गाजा में युद्धविराम में विस्तार करके इसे स्थाई युद्धविराम का दर्जा दिया जाना चाहिए। विश्व भर के देशों को अपनी दोहरी नीति को छोड़कर यह प्रयास करना चाहिए कि मध्य पूर्व में इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच के विवाद को स्थाई तौर पर हल करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। मिस्र के विदेश मंत्री ने स्पेन के विदेश मंत्री के साथ अरब इस्लामी कमेटी की बैठक के दौरान कहा कि फिलिस्तीनियों को गाजा से निष्कासित करने के लिए इजरायल द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसे रोकने के लिए विश्व के कुछ देश कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। गाजा में स्थाई युद्धविराम के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक इजरायल को यह अहसास न

हो कि युद्धविराम उसके हित में है। यह जरूरी है कि विश्व भर की शक्तियां एकजुट होकर इजरायल पर युद्धविराम के लिए दबाव डालें। गाजा में भेजे जाने वाली सहायता के मार्ग में इजरायल द्वारा जो रूकावटें डाली जा रही हैं, उससे समाधान खोजने में कठिनाई हो रही है।

मुंबई उर्दू न्यूज (23 नवंबर) के अनुसार सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने सभी देशों से अपील की है कि वे इजरायल को अस्त्र-शस्त्रों की सप्लाई करना बंद कर दें। इससे इजरायल को मजबूर होकर स्थाई युद्धविराम पर विचार करना पड़ेगा। उन्होंने यह राय ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब 1967 की सीमाओं के साथ फिलिस्तीनी रियासत की स्थापना के लिए एक गंभीर और स्थाई शांति की मांग करता है। उन्होंने कहा कि हमारा यह सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब गाजा बहुत ही मुश्किल स्थिति में है। हम गाजा में इजरायल के हमलों की निंदा करते हैं और पूरी ताकत से यह मांग करते हैं कि इन हमलों को रोका जाए। उन्होंने कहा कि इजरायल गाजा में बेकसूर नागरिकों, अस्पतालों और उपासना स्थलों पर वहशियाना हमले कर रहा है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि इस मानवीय त्रासदी को रोकने के लिए विश्व भर के देश सामूहिक रूप से प्रयास करें और स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकें। उन्होंने विश्व के देशों से अपील की कि वे गाजा को अधिक से अधिक सहायता उपलब्ध करवाएं। गौरतलब है कि ब्रिक्स देशों में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, मिस्र, रूस, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, इथियोपिया और ईरान शामिल हैं।

अवधनामा (23 नवंबर) के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियां ने ईरान में विभिन्न देशों के राजदूतों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने जोर दिया कि गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ इजरायल की जालिमाना युद्ध को रोकने के लिए विश्व की सभी शक्तियां एकजुट हों और यह मांग करें कि इजरायल द्वारा फिलिस्तीनियों को गाजा से निष्कासित करने का जो अभियान चलाया जा रहा है उसे रोका जाए। इसके साथ ही वहां पर मासूम नागरिकों के कत्लेआम को रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी संकट का एक मात्र हल यह है कि वहां पर जनमत संग्रह कराया जाए, ताकि फिलिस्तीनी अपने भविष्य का फैसला खुद कर सकें।

मुंबई उर्दू न्यूज (18 नवंबर) के अनुसार ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा है कि ईरान इजरायल के खिलाफ युद्ध में हमास की हर संभव मदद करेगा। उन्होंने हमास के सैन्य विंग के कमांडर मोहम्मद दीफ के नाम एक संदेश में कहा है कि हम इजरायल के खिलाफ युद्ध में हमास के साथ खड़े हैं। कुद्स फोर्स ने ईरान समर्थक हिजबुल्लाह, यमन और इराक में सक्रिय लड़ाकू संगठनों से आग्रह किया है कि वे एकजुट होकर इजरायल के खिलाफ कार्रवाई करें।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (21 नवंबर) के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनेई ने विश्व भर के मुस्लिम देशों से अपील की है कि वे इजरायल के साथ फौरन राजनयिक संबंध समाप्त करें और उसे तेल व खाद्यान्न की सप्लाई करना भी बंद करें। उन्होंने कहा है कि कुछ मुस्लिम देशों की सरकारों ने इजरायल की आक्रामक कार्रवाई की निंदा अपनी संसद में की है, लेकिन कुछ देशों ने अभी तक इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। गौरतलब है कि दो सप्ताह पहले सऊदी अरब में इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) और अरब लीग का एक संयुक्त अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ईरान ने सभी मुस्लिम देशों से इजरायल के साथ

राजनयिक संबंध समाप्त करने की अपील की थी। ईरान ने मुस्लिम देशों से यह भी अनुरोध किया था कि वे इजरायल को तेल की सप्लाई करना बंद कर दें। हालांकि, कई अरब देशों ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था। हाल ही में ईरान ने एक परेड़ के दौरान सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया था और यह दावा किया था कि यह मिसाइल इजरायल और अमेरिका के एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को विफल बना सकता है।

इत्तेमाद (20 नवंबर) के अनुसार तुर्किये के विदेश मंत्री हैकन फिदान ने कहा है कि इस क्षेत्र के सभी देशों को एकजुट होकर स्थाई युद्धविराम को लागू करने के लिए इजरायल पर दबाव डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समस्या का एक मात्र हल यह है कि 1967 की सीमाओं के आधार पर आजाद फिलिस्तीनी रियासत की स्थापना की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि तुर्किये ने गाजा पर इजरायल के हमले के बाद से लेकर अब तक मानवीय सहायता हेतु 11 विमान मिस्र के लिए रवाना किए हैं और तुर्किये के 170 नागरिकों को गाजा से निकाल लिया गया है। जबकि एक हजार से अधिक तुर्क नागरिकों को वहां से निकालने का प्रयास जारी है। सात अक्टूबर के हमले के बाद से हमने यह देखा है कि अभी तक वहां पर स्थाई शांति की स्थापना की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। हालांकि, 13 हजार से अधिक फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। हम इस कत्लेआम को मूकदर्शक बनकर नहीं देख सकते। हमारी यह नीति है कि गाजा में स्थाई शांति लागू हो और वहां के फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता पहुंचाई जाए।

तुर्किये के विदेश मंत्री ने कहा कि सभी इस्लामी देशों को गाजा के युद्ध को रोकने के लिए अपने राजनयिक और मानवीय हमदर्दी के साधनों का इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी चिंता प्रकट की कि इजरायल ने अब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देना शुरू कर दिया है। अब यह कोई गुप्त बात नहीं रह गई है कि अमेरिका और यूरोप के कई देश इजरायल की आक्रामक कार्रवाईयों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। जब तक इनके रूख में परिवर्तन नहीं होगा तब तक वहां पर कोई स्थाई शांति स्थापित नहीं हो सकती।

क्या गाजा में युद्धविराम के पीछे चीन का हाथ है?

हमारा समाज (21 नवंबर) के अनुसार चीन के निमंत्रण पर अरब और मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री बीजिंग पहुंचे थे। उन्होंने चीन से यह अपील की कि वह गाजा में युद्धविराम के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों में से एक है। सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलिस्तीन और ओआईसी के प्रतिनिधियों ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बीजिंग में मुलाकात की। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने

कहा कि हम यहां पर एक विशेष संदेश लेकर आए हैं। हम यह चाहते हैं कि गाजा में युद्धविराम को रोकने के लिए चीन अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। इस अवसर पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन अरब और मुस्लिम देशों का एक अच्छा दोस्त और भाई है। हमने हमेशा फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों का समर्थन किया है और उनके हितों की रक्षा के लिए हम प्रयासरत रहे हैं।

इससे पूर्व **सियासत** (20 नवंबर) ने यह दावा किया था कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने कहा है कि अरब और मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री चीन का दौरा करेंगे और इस दौरे का लक्ष्य गाजा में युद्धविराम को समाप्त करना है।

उर्दू टाइम्स (22 नवंबर) ने अपने संपादकीय में चीन की तारीफ करते हुए कहा है कि चीन दुनिया की राजनीति में विशेष भूमिका निभा रहा है। इसका ताजा उदाहरण बीजिंग में इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों और अन्य अधिकारियों की बैठक है। तमाम इस्लामी देशों का चीन में जमा होना इस बात का सबूत है कि चीन अरब देशों को कितना महत्व दे रहा है। पिछले दिनों चीन के प्रयास से ईरान और सऊदी अरब के बीच जो दोस्ती हुई है उससे साफ है कि चीन गाजा में युद्धविराम को रोकने के लिए बहुत गंभीर है। अब चीन में मुस्लिम देशों का जो सम्मेलन हुआ है वह अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। यह बैठक इस बात का साफ संकेत है कि इस्लामी देशों का चीन की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है। अब मुस्लिम देश चीन की ओर आशा की नजरों से देख रहे हैं। चीन भविष्य में सुपर पावर के तौर पर उभरकर अमेरिका को विश्व भर में साइड लाइन करना चाहता है। चीन ने अभी तक किसी भी मुस्लिम देश पर कोई हमला नहीं किया है। जबकि अमेरिका हमेशा अरब देशों में अपनी कठपुतली सरकारों को सत्ता में लाने का प्रयास करता आ रहा है। चीन को अरब देशों का जो समर्थन प्राप्त है उससे मुस्लिम जगत में एक नई आशा की किरण जगी है।

मुंबई उर्दू न्यूज (25 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका दौरा इसलिए किया क्योंकि दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका नाटो देशों के साथ मिलकर यूक्रेन को रूस का

कब्रिस्तान बनाना चाहता है। जबकि रूस गाजा में इजरायल और अमेरिका को उलझाकर यूक्रेन की जंग से विश्व का ध्यान हटाना चाहता है, लेकिन गाजा के युद्ध में इजरायल और अमेरिका बुरी तरह से फंस चुके हैं। अभी तक इजरायल गाजा में विजय प्राप्त करने में विफल रहा है। ऐसे में चीनी राष्ट्रपति ने इजरायल से साफ शब्दों में कह दिया है कि वह गाजा में युद्धविराम को संभव बनाने के लिए ठोस प्रयास करे, नहीं तो उसके लिए युद्ध को रोक पाना संभव नहीं होगा। चीन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका अपने नौसैनिक जहाजों को इजरायल की सहायता के लिए भेजता है तो वह भी इसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएगा।

समाचारपत्र का कहना है कि चीन के दबाव पर अब इजरायल अस्थाई युद्धविराम के लिए तैयार हो चुका है। हमास ने 100 के करीब इजरायली बंधकों और 70 से अधिक विदेशी बंधकों को अपनी कैद से रिहा कर दिया है। जो अस्थाई युद्धविराम चार दिनों के लिए था उसमें और भी वृद्धि की गई है। जरूरत इस बात की है कि इस युद्धविराम को स्थाई रूप दिया जाए। पूरी दुनिया में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका में भी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से मांग की है कि वे इजरायल पर युद्धविराम के लिए दबाव डालें, नहीं तो आने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में वे बाइडेन का समर्थन नहीं करेंगे। जिस तरह से चीन अरब मामलों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है उसे देखते हुए अमेरिका के लिए भविष्य में हूती विद्रोहियों को नियंत्रित कर पाना मुश्किल हो जाएगा। हाल ही में ईरान ने इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर अपने समर्थकों से जो हमले करवाए हैं उससे अमेरिका में काफी चिंता प्रकट की जा रही है। हालांकि, अमेरिका ईरान को निरंतर चेतावनी दे रहा है कि वह इस युद्ध को और हवा न दे। अमेरिका और इजरायल ईरान पर इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि वह इस युद्ध को मध्य पूर्व के अन्य देशों में फैलाने की कोशिश न करे। दूसरी ओर, ईरान ने अपने समर्थकों द्वारा अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज करवा दिए हैं।

ईरान से अफगान नागरिकों के निष्कासन का अभियान

सियासत (27 नवंबर) के अनुसार पाकिस्तान के बाद अब ईरान ने भी अपने देश मे रहने वाले अफगान नागरिकों के निष्कासित करने का अभियान तेज कर दिया है। जानकार सूत्रों के अनुसार अवैध रूप से ईरान में रहने वाले चार लाख से अधिक अफगान नागरिकों को वहां से निष्कासित किया जा चुका है। ईरान का दावा है कि ईरान में रहने वाले अफगान नागरिक आतंकी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। अफगानिस्तान सरकार के सूत्रों के अनुसार अफगानिस्तान की

सरकार ने ईरान से अफगान नागरिकों को निष्कासित किए जाने के अभियान की आलोचना की है और यह आरोप लगाया है कि ईरान की सरकार अफगान नागरिकों को जबरन अपने देश से बाहर निकाल रही है। समाचारपत्र के अनुसार हेरात में तैनात अफगान अधिकारियों का कहना है कि बहुत से अफगान नागरिकों को ईरान से जबरन निकाला गया है और उनके पासपोर्ट और वीजा को भी ईरानी अधिकारियो ने जानबूझकर फाड़ दिया है। अधिकारियों का यह भी आरोप है कि पासपोर्ट लेकर अफगान नागरिक ईरान में रोजगार की तलाश में गए थे।

जबकि ईरान सरकार का दावा है कि वह उन अफगान नागरिकों को देश से निष्कासित कर रही है, जिनके पास कोई पासपोर्ट या कानूनी दस्तावेज मौजूद नहीं है। अफगानिस्तान की एक पत्रिका ने ईरान से निष्कासित किए जाने वाले दो अफगान नागरिकों का बयान भी प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पास वैध पासपोर्ट और वीजा थे, इसके बावजूद वहां के अधिकारियों ने उन्हें जबरन ईरान से निकाल दिया है। ■

कतर में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों की फांसी के खिलाफ अपील

सियासत (25 नवंबर) के अनुसार कतर की एक अदालत द्वारा भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को दी गई फांसी की सजा के खिलाफ भारत सरकार की ओर से दायर अपील को कतर की एक अन्य अदालत ने स्वीकार कर लिया गया है। इस याचिका पर शीघ्र ही सुनवाई होने की संभावना है। भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार यह अपील 15 दिन पहले कतर की एक अन्य अदालत में दायर की गई थी। हालांकि, भारत सरकार या कतर ने अभी इस संबंध में कोई विधिवत सूचना नहीं दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नौ नवंबर को अपील दायर करने की सूचना दी थी और उन्होंने कहा था कि भारतीय दूतावास के अधिकारियों को इन आरोपियों से मुलाकात करने के लिए भी भेजा गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार कतर सरकार के निरंतर संपर्क में है।

गौरतलब है कि 16 अक्टूबर को कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के आठ पूर्व

अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई थी। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार इन पर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप है, मगर कतर सरकार ने इस संबंध में कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी है। कुछ दिनों पहले इन आरोपियों के परिवारजनों ने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी मुलाकात की थी। जानकार सूत्रों के अनुसार इन आरोपियों की मौत की सजा को माफ करवाने के लिए भारत तुर्किये की सरकार की भी सहायता ले रहा है।

यमन में भारतीय नर्स की मौत की सजा के खिलाफ अपील खारिज

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (18 नवंबर) के अनुसार यमन की सर्वोच्च न्यायालय ने केरल की रहने वाली एक नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा के खिलाफ दायर की गई अपील को रद्द कर दिया है। यह नर्स एक यमनी नागरिक की हत्या के आरोप में 2017 से यमन की जेल में बंद है। निमिषा पर यह आरोप है कि उसने एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या की है। कहा जाता है कि तलाल अब्दो महदी ने निमिषा का पासपोर्ट अपने कब्जे में रख लिया था और वह इसे वापस करने के लिए तैयार नहीं था। पासपोर्ट की वापसी के लिए निमिषा ने एक नशीला इंजेक्शन इस यमनी नागरिक को लगाया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी।

वहीं, निमिषा की मां ने यमन जाने की अनुमति के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रूख किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में एक सप्ताह के अंदर फैसला ले। निमिषा की मां अपनी बेटी को फांसी की सजा से बचाने के लिए 'ब्लड मनी' (मुआवजे की रकम) की धनराशि तलाल के परिवारजनों को देने के लिए तैयार है और वह इस संबंध में उनसे बातचीत करना चाहती है। याचिकाकर्ता की ओर से एक वकील सुभाष चंद्रन ने दिल्ली उच्च न्यायालय से यह अनुरोध किया था कि निमिषा को मौत की सजा से बचाने का एक मात्र रास्ता यह है कि उसकी मां को मृतक के परिवार के साथ सीधी बातचीत करने के लिए यमन जाने की अनुमति दी जाए, मगर यमन में गृह युद्ध को देखते हुए भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को यमन जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। निमिषा की रिहाई के लिए अभियान चलाने वाले एक संगठन सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय और केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया था कि विशेष परिस्थिति को देखते हुए निमिषा की मां को यमन जाने की अनुमति दी जाए।

RNI No. DELHIN/2017/72722

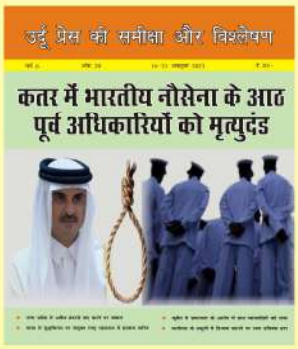

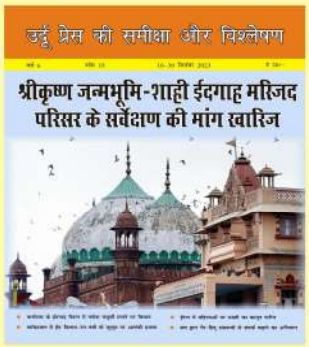

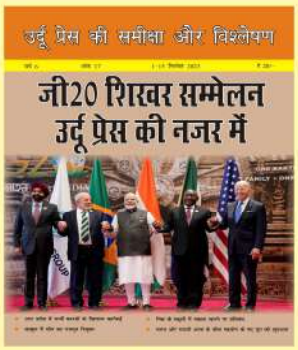

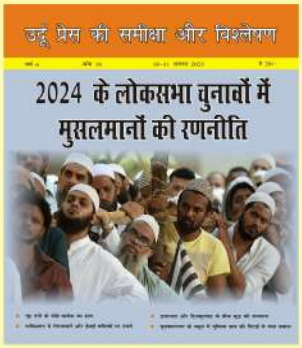

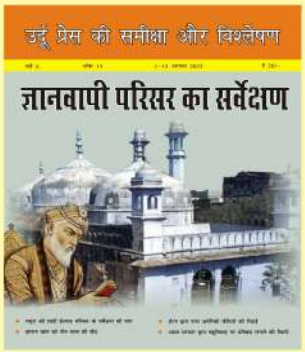

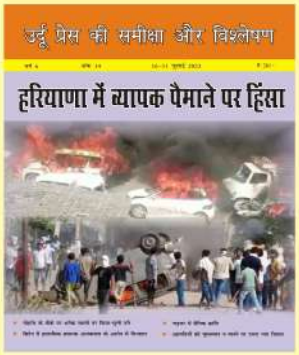

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in